SHRI MUFTI MOHAMMAD SAYEED: Sir, I must categorically say, for the information of the honourable Member, that as far as local direct recruit officers in the IAS and the IPS are concerned, there are a very few only, and the number is only nominal. That is why there is a great discontent in the administration.

MR. CHAIRMAN: Question No. 202.

फोन बीच में सुने जाने की जांच

*202. **श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल :** †
श्री मुरलीधर चन्द्रकांत भंडारे :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों तथा अन्य नेताओं के टेलीफोन बीच में सुने जाने तथा उनकी बातचीत चोरी छिपे सुने जाने के कथित आरोप के संबध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पूरी तरह कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी ।

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, is he the right Minister? I think the Home Minister would be the proper person to deal with this... (*Interruptions*)...Sir, this is an important matter, telephone-tapping, and it is done on the orders of the Home Ministry. So, don't you think that the Home Minister should be answering this question?... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The Communications Minister is doing it, he is answering it. That is all.

SHRI N. K. P. SALVE: Sir, this is a very important question. Which Ministry deals with telephone-tapping... (*Interruptions*)...and bigging? ...Is it the Home Ministry that deals with phone-tapping? Is it the Home Ministry or the Ministry of Communications?... (*Interruptions*)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, Mr. Salve should know better!... (*Interruptions*)...

SHRI N. K. P. SALVE: Sir, this that Ministry does not deal with it, who will give the reply?... (*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: There is no such thing. He is answering the question. That is all... (*Interruptions*)...

SHRI N. K. P. SALVE: Nonetheless, Sir, I would request you to consider this point... (*Interruptions*)...

SHRI DIPEN GHOSH: Sir, Mr. Salve should be knowing it... (*Interruptions*)...It is best known to Mr. Salve... (*Interruptions*)...

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Sir, he has raised a question and it has to be answered... (*Interruptions*)...

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, there should be no tapping in between supplementaries... (*Interruptions*)...

श्री एन० के० पी० साल्वे : चेयरमैन साहब, अगर मंत्री जी डील करते हैं, मान ले तो फिर माननीय सदस्य सवाल करें। **(व्यवधान)**

---

† सभा में यह प्रश्न श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल द्वारा पूछा गया।

SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: On the basis of my experience with this Government I say this. I am really not happy with the way in which answers are given. I have asked so many questions. The reply is always "No, Sir." or "It does not arise." This kind of language will be there. But when you ask the supplementaries, they come out with the information whereas they are supposed to give the information beforehand so that we may ask supplementaries. Sir, I seek your protection on this. I can quote examples.

MR. CHAIRMAN: No examples. The question is very simple. For "Whether the inquiry is completed", they say, "No, Sir." So far as the reply is concerned, we cannot find fault with it.

आप अपना सवाल पढ़िए ।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : ठीक है, मैं पूछता हूं । मेरा यह दोष है इस सरकार के ऊपर कि जब भी कोई मसला इनके सामने आता है, जिसका यह जवाब नहीं दे पाते ... **(व्यवधान)** ... आप अगर सुनेंगे तो समझ में आएगा, वरना नहीं । यह सरकार कमीशन बनाकर, कमेटी बनाकर, इन्क्वायरी बैठा कर उसको डिले करने की कोशिश करती है। श्री चन्द्र शेखर जी ने अपने इन्टरव्यू में कहा है कि "If I start revealing the truth, this Government will be in deep trouble." मेरा यह कहना है कि जब फ़ोन टैपिंग की बात राम कृष्ण हेगड़े की गवर्नमेंट के ऊपर आई तो उन्होंने रिजाइन किया ... **(व्यवधान)** ... सुप्रीम कोर्ट के फ़ॉरमर जज श्री एच० आर० खन्ना ने कहा कि

> "Ramakrishna Hegde's action in accepting moral responsibility for the affairs even as he disclaimed any involvement in it has been hailed as anethical step in the best traditions of democracy."

मेरा स्पेसिफ़िक क्वेश्चन है कि सी०बी० आई० से आप इन्क्वायरी करवा रहे हैं। सी० बी० आई० इज ए गवर्नमेंट एजेंसी । मिनिस्ट्री आफ़ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से ही पूछना है कि क्या आप फ़ोन टेपिंग करते हैं या नहीं करते हैं ? ज्यादा से ज्यादा चन्द्र शेखर जी से पूछेंगे कि आपका फ़ोन टेप होता है या नहीं, 27 नाम और कौन से हैं ? 7 अप्रैल से आपने सी० बी० आई० इन्क्वायरी शुरू की है, आज करीब सवा महीना हो गया है, मैं जानना चाहूंगा कि इन्क्वायरी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई, कब तक पूरी होगी, कितना टाइम और लगेगा ? या इसको आप डिले कर रहे हैं कि यह सैशन खत्म हो जाए, बाद में आए, शोर न मचे । मैं यह जानना चाहूंगा, स्पेसिफ़िक, कि यह इन्क्वायरी कब तक खत्म हो जाएगी ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मसला है और केवल आरोप-प्रत्यारोप से इसका कोई निर्णय नहीं हो सकता । जब तक पूरी छान-बीन नहीं हो जाती ... **(व्यवधान)** ...

श्री सभापति : वह पूछ रहे हैं कि छान-बीन कब तक हो जाएगी ?

श्री जनेश्वर मिश्र: यह तो सी० बी० आई० के लोग ही बता सकते हैं क्योंकि जांच उनको ही करनी है । जब वे सरकार को रिपोर्ट देंगे, उसके बाद इस सदन में उनकी रिपोर्ट और कार्यवाही रख दी जाएगी ।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब कृपया मुझे यह बताएं कि क्या सी० बी० आई० ने आपकी मिनिस्ट्री से इन्क्वायरी कम्प्लीट कर ली है ? अगर कर ली है, तो कब पूरी हुई है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : सी० बी० आई० टेलीफ़ोन टेपिंग के बारे में सारी जांच कर रही है और उसके बारे में वह हमारे मंत्रालय के अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है ।

श्री सभापति : अभी पूरी नहीं हुई है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : जी अभी पूरी नहीं हुई है ।

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Sir, this raises two very basic issues, the right of privacy of the citizen and the privileges of Members of Parliament. I have no doubt that this is going to be the Watergate of the value-based V.P. Singh Government. In the first instance, I think this question is really not appropriate for the Minister of Communications...

श्री सभापति : तो आप सवाल कर लीजिए। दूसरी मिनिस्ट्रीज के बारे में क्यों कह रहे हैं?

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: I am coming to it. He is not even concerned about the violations of the Indian Telegraph Act and he is going to sit with folded hands and wait for the CBI to complete the inquiry. I think this is not at all the attitude of somebody who is in charge of implementing the Indian Telegraph Act. Now, one specific question I want to ask is, have you asked the persons who are permitted under section 5(2) of the Indian Telegraph Act to tap telephones under special circumstances and have you handed over to the CBI a list of the names you have cleared for tapping of their phones and, if so, who are included in that list?

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति जी, सैक्शन 52 में उन टेलीफ़ोनों के बारे में जांच करने के साथ-साथ एक लाइन लिखी हुई है जिनके टेलीफ़ोन टैप होते हैं। जो राजनेताओं की शिकायतें आई हैं विशेषकर चन्द्रशेखर जी की, उसके बाद ही यह सी. बी. आई. की इन्क्वायरी बिठाई गई है और बगल वाले सदन में इस मामले को प्रिविलेज कमेटी को भी रैफ़र कर दिया गया है। जहां तक आदमी की प्राइवेसी का सवाल है, सरकार अपनी मूल्य निर्धारित राजनीति के वायदों पर टिकी हुई है क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम विपक्ष में थे और इस तरह की शिकायत करते थे तो कोई भी जांच करने का हुक्म सरकार की तरफ़ से नहीं हुआ करता था।

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: This is no reply. He does not know the Indian Telegraph Act.

श्री सभापति : उनका सवाल तो सुनिए ... (व्यवधान)

श्री जनेश्वर मिश्र : चूंकि यह सवाल केवल एक संसद सदस्य माननीय चन्द्रशेखर जी ... (व्यवधान) इसका जवाब देना जनहित में उचित नहीं होगा।

श्री सभापति : वह कह रहे हैं कि इसका जवाब देना जनहित में ठीक नहीं है।

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: I have asked, who is the authority under section 5(2), whether such a list exists and have you handed over the list to the CBI? I am afraid that this list is not to be tampered with... (*Interruptions*)

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति जी, सैक्शन 52 में सेन्ट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ अफ़िशियल्स हैं जो यह जांच कर सकते हैं—
Director of Intelligence Bureau, Director-General of Revenue Intelligence, Director-General of Economic Offences, Director of Enforcement, Director of Central Narcotics Bureau, in the State Government the Chief Secretary or any officer of DIG rank.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: I am not satisfied at all. (*Interruptions*)

श्री सभापति : उन्होंने पूछा है कि जिनके टेलीफ़ोन टैप किए जा रहे हैं उनकी लिस्ट क्या आपने सी. बी. आई. को दे दी है?

श्री मुरलीधर चन्द्रकांत भंडारे : आपने लिस्ट दी कि नहीं, कि इनके टेलीफ़ोन टैप करने के आर्डर आए हैं।

श्री जनैश्वर मिश्र : देखिए, जांच केवल सैक्शन 5? की धाराओं के तहत ... (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: Have you given to the CBI a list of those whose telephones you should tap? That's all. Say 'yes' or 'no'; that's all.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. UPENDRA): Is it regular tapping or misuse of tapping?... (*Interruptions*)

AN HON. MEMBER: He said 'No', Sir... (*Interruptions*)

श्री जनैश्वर मिश्र : नहीं दी है।

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Second supplementary...

MR. CHAIRMAN: No, no. The Rules are very clear. (*Interruptions*)

SHRI DIPEN GHOSH: Never is it allowed... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Dipen Ghosh.

SHRI DIPEN GHOSH: Mr. Chairman, Sir, this is a very serious matter. When the tapping of telephones was earlier discussed in this House, we were opposed to the existence of the very system that there should be bugging of telephones of others. It would mean that the Government should be given the right of interference into the privacy of citizens. The question is whether the C.B.I. has completed the inquiry. The reply is "No". The specific matter which relates to the bugging of the telephone of a particular Member of Parliament or of some Members of Parliament has been referred to the Privileges Committee of the other House. My specific question is this. Since this Government is committed to uphold the democratic institutions and the rights and privileges of the citizens, is this Government prepared to bring in an amendment to the Indian Telegraph Act for the purpose of cutting at the very source of tapping or bugging of the telephones?

श्री जनैश्वर मिश्र : सरकार टेलीफोन टेपिंग और बगिंग के बारे में कौन से वह नियम बनाये जायें जिससे कि इसका दुरुपयोग न हो, विचार कर रही है।

श्री यशवन्त सिन्हा : मान्यवर, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं और दो खण्ड में मेरे सवाल हैं, एक तो यह है कि इनका जो मंत्रालय है कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, क्या इनके मंत्रालय की जानकारी के बिना ही यह संभव है कि कुछ एजेंसियां टेलीफोन टेपिंग कर सकती हैं ? क्या कम्युनिकेशन मिनिस्टर की बिना जानकारी के भी यह संभव है कि टेलीफोन टेपिंग हो रहा है ? एक तो मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं। अगर उसका उत्तर यह है कि इनकी जानकारी के बिना नहीं हो सकती है तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आप सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जो क्रिमिनल की कैटेगरी में आते हैं, आफेंडर्स की कैटेगरी में आते हैं क्या मंत्री महोदय इस सदन में यह कहने की स्थिति में हैं कि किसी राजनीतिक नेता या व्यक्ति का टेलीफोन आज सरकार टैप नहीं करवा रही है ? क्या यह आश्वासन या कहने की स्थिति में मंत्री महोदय हैं ?

श्री जनैश्वर मिश्र : सभापति महोदय, टेलीफोन टेपिंग के संबंध में आम तौर से हमारे मंत्रालय को फर्माइश आती है दूसरे मंत्रालयों से, लेकिन हमारे मंत्रालय को भी उसकी जानकारी होती है। किसी राजनीतिक नेता के टेलीफोन टेपिंग हो, न हो, इस बात की जब कभी भी शिकायत आती है उसके दुरुपयोग की तो उसकी जांच करायी जाती है और उसी की जांच कराने के लिये यह मामला सी.बी.आई. को दिया गया।

SHRI KAMAL MORARKA: Sir I need your protection. This does not answer the question of Mr. Sinha.

MR. CHAIRMAN: Mr Sinha is satisfied.

SHRI KAMAL MORARKA: But the House is not satisfied. Sir, if I am permitted to put the question in perspective, the whole House will be enlightened. Mr. Sinha has asked two things He has asked whether there is equipment available in the country Is there equipment available with any of these various agencies which the Minister has named which enables them to tap the telephones without informing the Communications Ministry at all? Is there such equipment available? Is it technically possible? If it is, then he will never know what they are doing. Secondly, he should categorically tell the House whether according to Section 52, apart from criminals, economic offenders, terrorists, etc., the Government has authorised the tapping of the telephones of any political personality It is simple.

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति महोदय, ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है । मैंने शुरू में बताया इसकी जानकारी हमारे मंत्रालय को दूसरे मंत्रालय दे देते हैं । लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या जो इस श्रेणी में आते हैं धारा-52 के उसके अलावा भी किसी की टैपिंग होती है ? तो मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि इस तरह की कोई भी टैपिंग नहीं होती है ।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : मंत्री महोदय, अगर टैपिंग नहीं होती है तो सी०बी० आई० इंक्वायरी की क्या जरूरत है ? (व्यवधान)

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, first I will request the Minister to reply to me in English because I do not follow Hindi correctly.

आप कितना ब्रीफ करेंगे उपेन्द्र जी, You are the Minister of Parliamentary Affairs. You brief every Minister. फिर क्या बात हैं. . .

श्री सभापति : आप सवाल पूछिये ।

SHRI A. G. KULKARNI: I am doing, Sir. He is briefing him. I seek your protection.

MR. CHAIRMAN: You can get brief from him also.

SHRI A. G. KULKARNI: I do not want Mr. Upendra's brief. I am quite competent myself.

MR. CHAIRMAN: Now put your question.

SHRI A G. KULKARNI: Sir, I want to ask him two questions. Firstly, Sir, I do not think there is any Watergate involved in this. Nothing will happen. It is there right from the days of Chanakya. You are coming from Allahabad. These things are going on and राजनीति में ऐसा ही होता है । So, there is not much of a problem in tapping. Tapping is done all the world over. So, one should not get scared. My question to him is this: When the CBI started enquiry, have those people who have complained co-operated with the CBI in giving their statements, and has the CBI interviewed many political and other personalities who are being named in this tapping? Secondly, Mr. Minister, you again think yourself. It was Mr. Upendra as Minister of Parliamentary Affairs and my friend, Mr. Unni Krishnan as Minister of Communications who have categorically stated that they would bring a Bill for stopping this pernicious system of tapping the telephones. That is their assurance. And now you say विचार कर रहे हैं । You, as an intelligent man from Allahabad must be able to know what happens when assurances are given. I want to know whether you will again rectify, correct your mistake, and say that the Bill is being brought as assured on behalf of your Government by these two stalwarts sitting here.

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति जी, भाषा के मामले में हमारा निजी ख्याल है. . .

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : अंग्रेजी में बोलिए ।

श्री सभापति : यह अंग्रेजी भी बहुत अच्छी जानते हैं। हिन्दी में बोलना चाहते हैं तो हिन्दी में सुन लीजिए।

श्री जनेश्वर मिश्र : मैं हिन्दी में बोलना चाहता हूं। मेरा निजी ख्याल है कि विदेशी भाषा का इस्तेमाल सार्वजनिक मंच से नहं करूंगा। मैं डा. लोहिया के साथ रहा हूं और मेरा यह... (व्यवधान)

श्री सभापति : सबको यह अधिकार है कि वह हिन्दी में बोले या अंग्रेजी में बोलें।

श्री जनेश्वर मिश्र : माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या सी०बी०आई० जिन लोगों से जांच कर रही है इम्पोर्टेंट लोगों से उन लोगों में से कुछ ने अपने टेलीफोन टैपिंग के बारे में बताने से इन्कार किया, या किन-किन लोगों से जांच कर रहे हैं, कब से जांच शुरू हुई है, और सी. बी. आई. की जांच के बारे में बताना सदन में मैं समझता हूं उचित नहीं है। (व्यवधान)

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, what is this? It is a simple question. This is not a State secret. I wanted to know whether anybody refused to give a statement.

श्री जनेश्वर मिश्र : जांच की प्रक्रिया के बारे में कुछ भी बताना ठीक नहीं होता अगर ऐसा होगा तो गुप्तचर जांच नहीं रह जायेगी। अगर हम लोग यहां जांच प्रक्रिया पर बहस करेंगे .... (व्यवधान)

श्री सभापति : यह पूछ रहे हैं कि क्या कुछ लोगों ने कोआपरेट करने से इंकार किया है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : लोग कोआपरेट कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो माननीय सदस्य ने पूछा है माननीय उन्नीकृष्णन और पी० उपेन्द्र जी ने दोनों ने सदन में आश्वासन दिया है कि टेलीफोन टैपिंग का दुरूपयोग न हो इसके लिए नियम, कानून में परिवर्तन किये जायेंगे। हमने शुरू में कहा था कि उन्हीं लोगों के आश्वासन चलते हम इस सवाल पर आपस में विधि मंत्री और गृह मंत्री से विचार-विमर्श कर रहे हैं।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Mr. Chairman, Sir, this is a most important question because it is not only anti-democratic, but it also gives rise to forces of authoritarianism in the country. The right of the people is denied by this.

MR. CHAIRMAN: Put your supplementary.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: This being the preface, I certainly object to the way in which the Minister is dealing with the questions.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: I agree with you.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Absolutely. He is dealing very lightly with the questions that are being put to him even by the Members of his own party. He can straightaway say that the Government has not made up their mind. I can very well understand if he says so. But I object to the way in which he is answering the questions. This sort of 'hide-and-seek' game was there in the House previously I would like to know whether this Government wants to continue this. Therefore my specific questions are: whether tapping used to be done previously by the earlier Governments, whether tapping on political grounds continues till now and whether the Government believes that tapping on political grounds is draconian and that it should be dispensed with. This is a matter of principle. Let him say straightaway. Let him say 'Yes' or No'. Let him not evade.

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति महोदय, पोलिटिकल ग्राउन्ड पर कोई भी टैपिंग नहीं होती है। अगर उसका कहीं दुरूपयोग होता है तो उसकी जांच की जाती है।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: This means, Mr. Chandra Shekhar has given a false allegation to the Government. By implication, he is meaning it.

MR. CHAIRMAN: Don't bring in his name. He is a Member of the other House.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि टैपिंग करने के बकायदा डिपार्टमेंट्स हैं और जो अफसरान उन्होंने बताये हैं वे अलग अलग टैपिंग करते हैं या कहीं पर गृह मंत्रालय के अधीन इकट्ठा दिल्ली में होता है ? साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इसी प्रकार के अधिकारी अन्य प्रदेशों में भी अधिकृत हैं और विशेषकर बंगाल के बारे में आपका क्या कहना है कि वहां पर टैपिंग होती है या नहीं होता है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति महोदय, जिन विभागों के बारे में मैंने बताया है उनके अधिकारी टैपिंग करते हैं और सरकार की तरफ से अधिकृत हैं । वे अलग-अलग टैपिंग करते हैं । जिस सूबे के बारे में पूछा गया है कि टैपिंग होती है या नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी इकठी करनी पड़ेगी । वैसे पोलिटिकल टैपिंग आमतौर पर नह होती है ।

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY. Sir, I would like to draw the attention of the Government, particularly, that of the Minister, to section 5(2). It says that the reasons for wanting to tap a telephone will be given in writing. I do not know whether he has read this. It is very clear there. I would like to know whether, in view of the fact that in the Karnataka case...It is very relevant. You will see, Sir. In view of the fact that in the Karnataka case where the Chief Minister disowned responsibility after having ordered the tapping and put the blame on the officer...

MR. CHAIRMAN: Karnataka case is not relevant here. *(Interruptions)*

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, this should not be permitted. *(Interruptions)*

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: I would like to know whether the Government would require... *(Interruptions)*

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, this should be expunged.

MR. CHAIRMAN: Mr. Swamy, I told you, Karnataka case is not relevant here. *(Interruptions)*

SHRI VIREN J. SHAH: This is a deliberate defamation and, therefore, it should be expunged.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: I would like to know whether the Government would require that while giving the reasons in writing...

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: It is not relevant to the main question. *(Interruptions)*

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Now the reasons are to be giving in writing when political authorities' or political personalities' telephones are tapped. I want to know whether Government would consider an amendment to the regulations that when political persons' or Members of Parliament's telephones are to be tapped, the political authority—the Minister or the Chief Minister—must himself in writing, as in England and other places, give the order and not shift the blame on to the officers. To protect the officers, I say that when a politician's telephone is tapped, the poltical authority must put his signature and say that the telephone tapping is required. I would like to know whether he would consider that amendment.

MR. CHAIRMAN: That is a suggestion for action.

श्री जनेश्वर मिश्र : टेलीफोन टैपिंग में दुरुपयोग न हो, इसको रोकने के लिये जो संशोधन की बात चल रही है, उसमें माननीय सदस्य का जो सुझाव है, उस पर गौर किया जायेगा ।

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, the hon. Minister has stated that the CBI enquiry has not been completed. I would like to know from the hon. Minister whether the CBI is also enquiring into the telephone-tapping of politicians that was made during the period 1985—89. Sir, I bring to your notice that there was complaints galore from M.L.As. and M.Ps. in various States and in Delhi that their telephones were being tapped.

MR. CHAIRMAN: Your question is whether there was tapping in the previous period.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Just like in Karnataka.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Okay, as in Karnataka. But this happened in other States, including M.Ps. in Delhi, during that period. I would like to know from the hon. Minister whether the enquiry covers that period as well.

श्री जनेश्वर मिश्र : सी०बी०आई० की इन्क्वायरी अतीत के बारे में नहीं है बल्कि वर्तमान में जो शिकायतें आई हैं उनके बारे में हैं ।

SHRI S. JAIPAL REDDY: No, Sir ...Mr. Chairman, Sir...I am recalling to you, Sir...The Minister is not being correct...No, Sir.

MR. CHAIRMAN: Question No. 203. I have to depend on the answer of the Minister.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, he must state the facts...Mr. Upendra made a statement at that point of time that the CBI was enquiring into telephone tapping of not only this period but also of the previous period.

MR. CHAIRMAN: Question No. 203.

SHRI S. JAIPAL REDDY: No, Sir. I want the Minister...

MR. CHAIRMAN: I have put Question No. 203...I have called Question No. 203. What is there to say, "No, Sir"?

SHRI S. JAIPAL REDDY: But, Sir, let him clarify...

MR. CHAIRMAN: I have called Question No. 203.

जम्मू और कश्मीर सम्बंधी समिति

@*203. **श्री सैयद सिब्ते रजी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल किये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए एक समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) समिति के विचारार्थ विषय क्या है ;

(घ) इसका गृह मंत्रालय से क्या संबंध होगा और समिति के कार्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या समिति राज्य में सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देगी , और

(च) यदि हां, तो जम्मू और कश्मीर सरकार को जारी किये जाने वाले निर्देशों की संवैधानिक स्थिति क्या होगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (च) कोई समिति गठित नहीं की गयी, तथापि जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित मामलों

@Previous starred Question 23 Postponed from 2-5-1990.